MR. CHAIRMAN: Please answer one question.

SHRI SACHIN PILOT: Sir, the supplementary question does not relate to this question. If he wants any specific details, I would request him to meet me and give me in writing. I will submit those details to him.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि BSNL के नेटवर्क की जो हालत है, क्या ये खुद BSNL का यूज करते हैं या किसी और कंपनी का कनेक्शन ले रखा है? हम मंत्री जी से हाउस में यह एश्योरेंस चाहते हैं कि BSNL के नेटवर्क की जो व्यवस्था है, वह बहुत पुअर है। आपने यह तो कर दिया गया है कि कॉल चार्जेस एक मिनट की बजाय एक सैकिण्ड पर आ जाएंगे...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सवाल पूछ लीजिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: क्या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कोई एफ्टर्स जुटाए जाएंगे? क्या इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा? धन्यवाद।

SHRI SACHIN PILOT: Sir, again this supplementary does not relate to the main question directly. But I can assure the hon. Member, through you, Sir, that the problems we face सभापति जी, ग्रामीण क्षेत्र में हमें ज्यादा दिक्कत आती है। जो मोबाइल के टावर होते हैं, वहां पर कभी-कभी बिजली की सप्लाई नहीं होती है। बिजली की सप्लाई नहीं होने से वे टावर्स काम में नहीं आ सकते हैं। हमने वहां व्यवस्था की है। हम लोग जनरेटर देते हैं, डीजल भी उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन अगर पावर सप्लाई बेहतर होगी..

श्री साबिर अली: सभापति जी, बिहार में...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइए। आप जवाब सुन लें। ...(**व्यवधान**)...

श्री साबिर अली: सभापति जी...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: साबिर अली जी, आप बैठ जाइए प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए, आप जवाब सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... आप जवाब सुन लीजिए, आपकी बारी नहीं आई है।

श्री सचिन पायलट: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ ...(**व्यवधान**)... मेरा निवेदन है कि अगर मोबाइल टावर्स को सही बिजली उपलब्ध होगी, तो निश्चित रूप से वे काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी-अपनी राज्य सरकारों से भी निवेदन करें कि वे बिजली का उत्पादन बढ़ाएँ, ताकि हमारे मोबाइल टावर्स काम कर सकें।

पिछड़े राज्यों का विकास

*107. **श्री रवि शंकर प्रसाद**:
श्री शिवानन्द तिवारी:††

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अपनी प्रति व्यक्ति आय और वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003 से 2008 तक की अवधि में इन राज्यों में अनुमानित प्रति व्यक्ति औसत आय और वार्षिक वृद्धि-दर कितनी-कितनी रही है;

---

††सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।

(ग) क्या राष्ट्र के सन्तुलित विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर इन राज्यों का विकास करना अनिवार्य है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2003 से 2008 की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि में, बिहार, मध्य प्रदेश, असम राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत आय से कम हुई है। वर्ष 2003 से वर्ष 2008 की अवधि के लिए कारक लागत (1999-2000 के मूल्यों पर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वार्षिक विकास दर के आधार पर राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के औसत से कम है।

(ख) वर्ष 2003-08 के दौरान इन राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय और वार्षिक विकास दर का ब्यौरा विवरण -I में दिया गया है (**नीचे देखिए**)

(ग) और (घ) सरकार देश भर में संतुलित तरीके से विकास दर में सुधार करने के लिए अनेक उपाय करती रही है। इससे संबंधित नीतिगत उपायों के अंतर्गत कम विकसित राज्यों का समर्थन करते हुए केन्द्र से योजना और गैर-योजना संसाधनों का अंतरण, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगों की स्थापना के लिए कर प्रोत्साहन आदि शामिल है। राज्यों के बीच आय असमानता कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू कर किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि शामिल है।

विवरण-I

तालिका: प्रति व्यक्ति आय और वार्षिक विकास दर

प्रति व्यक्ति आय (रुपए)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	औसत (2003-08)
बिहार	6117	6772	6719	8167	8703	7296
मध्य प्रदेश	11870	12032	12567	12881	13299	12530
असम	13675	13946	14419	15152	15857	14610
राजस्थान	15579	14908	15577	17143	18095	16260
उत्तर प्रदेश	10120	10421	10758	11334	11939	10914
अखिल भारत	18301	19331	20868	22580	24295	21075

वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	औसत (2003-08)
1	2	3	4	5	6	7
बिहार	-5.15	12.17	1.49	22.00	8.04	7.7

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	11.42	3.08	6.48	4.75	5.25	6.2
असम	6.02	3.74	4.94	6.97	6.06	5.5
राजस्थान	28.67	-1.85	6.89	11.81	7.33	10.6
उत्तर प्रदेश	5.27	5.4	5.25	7.18	7.16	6.1
अखिल भारत	8.52	7.47	9.52	9.75	9.01	8.9

स्रोत: सीएसओ (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) आंकड़े दिनांक 27.10.2009 के अनुसार

Development of backward States

†107. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:
SHRI SHIVANAND TIWARI:††

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the States of Bihar, Madhya Pradesh, Assam, Rajasthan, Uttar Pradesh, etc. are backward on the basis of their per capita income and annual growth rate;

(b) if so, the average per capita income and annual growth rate estimated in these States during the period from 2003 to 2008;

(c) whether the development of these States on a priority basis is necessary for the balanced growth of the nation; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In terms of per capita income for the period 2003 to 2008, the States of Bihar, Madhya Pradesh, Assam, Rajasthan and Uttar Pradesh fell below the national average per capita income. On the basis of annual growth rate of Gross State Domestic Product (GSDP) at factor cost (at 1999-00 prices) for the period 2003 to 2008, all the States except Rajasthan fell below the national average of Gross Domestic Product (GDP) growth rate.

(b) A statement of the average *per capita* income and annual growth rate estimated in these States during the year 2003-2008 is given in the Statement-I (*See* below).

(c) and (d) The Government has been taking several measures to improve the growth rate across the country in a balanced manner. The policy instruments in this regard nclude plan and

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari.

non-plan transfer of resources from the Centre to States favouring less developed States, tax incentives for setting up of private industries in the backward regions, etc. A number of programmes have been initiated to reduce income disparity between States. These include Backward Regions Grant Fund (BRGF), Hill Area Development Programme and Border Area Development Programme, etc.

Statement-I

Table: Per capita Income and Annual Growth Rates

Per Capita Income (Rs.)

States	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Average (2003-08)
Bihar	6117	6772	6719	8167	8703	7296
Madhya Pradesh	11870	12032	12567	12881	13299	12530
Assam	13675	13946	14419	15152	15857	14610
Rajasthan	15579	14908	15577	17143	18095	16260
Uttar Pradesh	10120	10421	10758	11334	11939	10914
ALL INDIA	18301	19331	20868	22580	24295	21075

Annual Growth Rates (%)

States	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Average (2003-08)
Bihar	-5.15	12.17	1.49	22.00	8.04	7.7
Madhya Pradesh	11.42	3.08	6.48	4.75	5.25	6.2
Assam	6.02	3.74	4.94	6.97	6.06	5.5
Rajasthan	28.67	-1.85	6.89	11.81	7.33	10.6
Uttar Pradesh	5.27	5.4	5.25	7.18	7.16	6.1
ALL INDIA	8.52	7.47	9.52	9.75	9.01	8.9

Source: CSO (Central Statistical Organization): Data as on 27.10.2009

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, हमारे देश के संविधान में यह दिशा निर्देश दिया गया था कि जो क्षेत्रीय गैर-बराबरी है, उसको सरकारें मिटाने की कोशिश करेंगी। जो लक्ष्य संविधान ने तय किया था, आजादी के 62 वर्षों के बाद उसकी क्या हालत है, वह मंत्री जी के जवाब से जाहिर है। अगर हमारे यहाँ देखा जाए, तो जो प्रति व्यक्ति आय है, वह देश में 2003 से 2008 के बीच 21,075 रुपए है, दूसरी तरफ बिहार में 7,296 रुपए है और उत्तर प्रदेश, जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी प्रति व्यक्ति आय 10,914 रुपए है। इतनी बड़ी आबादी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से इतना नीचे है, तीन गुना नीचे है, आधे से अधिक नीचे है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि संविधान ने क्षेत्रीय गैर-बराबरी को दूर करने का जो लक्ष्य

निर्धारित किया था, वह क्षेत्रीय गैर-बराबरी दूर नहीं हो रही है, इसका ऐतिहासिक कारण क्या है? क्या सरकार ने इसका कोई अध्ययन करवाया है और क्या सरकार कोई योजना बना कर उन कारणों को दूर करने का प्रयास करने जा रही है?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, to consider and, then, to take remedial measures for bridging the gap between the developing States and the underdeveloped States, as the hon. Member has mentioned, to remove regional imbalances, during the Tenth Plan Mid-term Appraisal, a discussion was held, and thereafter, a Task Group was formed by the Planning Commission in August, 2004. Then, the Task Group submitted a Report to the Government, and on that basis, the Backward Regions Grant Fund was created. About 250 districts have been identified as backward districts in the country. If I can tell you State-wise the number of districts which has been selected, Bihar, 36 districts; Assam, 10 districts; Madhya Pradesh, 24 districts; Rajasthan, 12 districts and Uttar Pradesh, 34 districts. An amount of Rs. 4,670 crores was allocated in the Eleventh Plan. And, the districts were given money for the purpose of developing road infrastructure, water supply facility, sanitation and other basic amenities required for the rural people in the backward region. Then, Sir, apart from that, as far as Bihar is concerned, looking into the backwardness of the region, a Special Package, amounting to Rs. 1,000 crores, has been given by the Government of India, and that money has to be utilized for irrigation, watershed management, power, road connectivity and forestry. Every year this money is being given. So, for the last three years, it has been continuously given to the Government of Bihar. Sir, the Plan and Non-Plan Budget provision is one thing, and the Centrally-sponsored Schemes is another thing. Apart from that, special funds have been created by the Government.

The hon. Members from the State of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh mentioned about the Bundelkhand region. The Government of India has provided Rs. 7,600 and odd crores as the Bundelkhand package. Therefore, the Government is committed to the development of the backward regions in the country. Look at the figures pertaining to the GDP. Bihar had 1.9 per cent earlier and now it is 7.7 per cent. Next year, it was 22 per cent; it was much less in the previous year. As far as Madhya Pradesh is concerned, it was 4.75 per cent in 2006-07; now it is 6.2 per cent. As far as Assam is concerned, it is 5.5 per cent. As far as Rajasthan is concerned, it was 7.33 per cent earlier and it has now gone up to 10.6 per cent. In the case of Uttar Pradesh, it was 7.16 per cent, which has now come down to 6.1 per cent. Sir, the Government of India is alive to these regional imbalances and it has been addressing these issues from time to time.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Tariq Anwar.

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, मेरा एक सवाल और बनता है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आपका हक़ एक सवाल का है ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, मेरा एक सवाल तो बनता ही है ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, पहला मैम्बर अगर नहीं आया तब दूसरा मैम्बर दो सवाल पूछ सकता है ...(**व्यवधान**)...।

MR. CHAIRMAN: The ballot is in the first person; he is only associating. ...*(Interruptions)*... I am very clear about it.

श्री शिवानन्द तिवारी: नहीं सर, मेरा एक सवाल तो बनता है। मैं इस देश के सबसे पिछले प्रदेश से आता हूं ...(**व्यवधान**)... यह एक महत्वपूर्ण सवाल है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यह हाउस की प्रैक्टिस का सवाल है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: शिवानन्द जी, एक मिनट ...(**व्यवधान**)...।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, कम से कम हमको यह अधिकार मिले कि हम दो सवाल पूछ सकें। एक पूछ लिया है और एक हमको पूछ लेने दीजिए ...(**व्यवधान**)...।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, तिवारी जी, सवाल वह नहीं है ...(**व्यवधान**)... इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां इतनी भयानक हालत है, इसलिए सभापति महोदय, हमको एक सवाल पूछने दिया जाए ...(**व्यवधान**)...।

श्री सभापति: तिवारी जी, सवाल वह नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सवाल वह नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, हमको इससे वंचित नहीं किया जाए ...(**व्यवधान**)...।

श्री सभापति: देखिए, जहां तक हाउस की प्रैक्टिस का सवाल है ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: यह सरकार तो पिछड़े इलाके का शोषण कर ही रही है, सभापति महोदय, यदि आप भी ऐसा कीजिएगा, तो हम लोग कहां जाएंगे।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, if he doesn't turn up...*(Interruption)*...

MR. CHAIRMAN: I am sorry, the ballot is in the first person.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir. If he doesn't turn up, the second man becomes the first.

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is the convention of the House.

MR. CHAIRMAN: I will allow this question but this is against the rule, clearly. Please, go ahead. And I would request both the hon. Minister and...

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति जी, अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने आंकड़ों का जो जाल यहां पर पेश किया कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार अमुक-अमुक काम करने जा रही है। यह एक भ्रम जाल है। देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है – एक बीमारू और एक स्वस्थ। पता नहीं स्वस्थ भी वे कितने हैं। जब स्वस्थ राज्यों के किसानों की आत्महत्या के बारे में खबर मिलती है, तो हम लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में भी संदेह होता है। लेकिन ये जो बीमारू राज्य हैं, एक तरफ 21,075 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है और दूसरी तरफ 7,296 रुपये है। आप जो उपाय बता रहे हैं, क्या उससे यह गैर-बराबरी दूर होगी?

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, जो पिछड़े राज्य हैं, उनके साथ ट्रैजेडी यह है कि वहां इन्वैस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। वहां कोई प्राइवेट इन्वैस्टर नहीं जा रहा है। सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना

से लेकर आज तक सबसे कम निवेश इन राज्यों में किया है, जो बीमारू माने जाते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बड़े पैमाने पर...। आप जो बता रहे हैं, उसमें गलत बात यह है कि हमारी बिहार की सरकार ने नैशनल हाईवे पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है, लेकिन आपने आज तक नहीं दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए, ताकि वे जवाब दे सकें।

श्री शिवानन्द तिवारी: कोई भी केन्द्रीय निवेश इन राज्यों में बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री शिवानन्द तिवारी: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके बगैर यह गैर-बराबरी कैसे दूर हो सकती है?

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Minister to give a short, pointed answer. This is not debate. This is Question Hour.

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Chairman Sir, I understand the anguish of the hon. Member. But as far as the development of the backward regions is concerned, and the implementation of various schemes by the State Governments in rural areas is concerned, for supplementing the Budget proposals that have been given, the Centrally-sponsored schemes which have been implemented by the State Governments and for which funds have been provided by the Central Government, various schemes like the National Rural Employment Guarantee Scheme, Sarva Shiksha Abhiyan, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, National Rural Health Mission...

श्री शिवानन्द तिवारी: यह तो पूरे देश के लिए है, लेकिन इन क्षेत्रों के बारे में स्पैसिफिक ढंग से आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप वहां किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं या नहीं, हम लोग यह जानना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: I have specifically mentioned, Sir, the Special Plan for*...(Interruptions)...*

श्री शिवानन्द तिवारी: नहीं तो सारे BIMARU राज्य एक साथ खड़े होंगे और केन्द्र से लड़ेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: आपने उनको उपनिवेश बनाकर रखा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पाणि जी, आप बैठ जाइए...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: कॉलोनीज़ हैं, ये पिछड़े राज्य! ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please. *...(Interruptions)...* Hon. Members, there is an occasion for agitation, but Question Hour is not the occasion for agitation. Let us stick to the established practices of this House - ask questions and receive answers. *...(Interruptions)...*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Brief answers from the Ministers.

MR. CHAIRMAN: Fair enough. *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as far as poverty ratio is concerned, I would like to bring it to the notice of the hon. Member that the all-India average is 27.5 per cent. In Bihar, in 1993-94,

it was 55 per cent, which has come down to 41 per cent. In Assam, from 40.9 per cent, it has come down to 19.7 per cent. In Madhya Pradesh, from 42.5 per cent, it has come down to 38.3 per cent.

SHRI SITARAM YECHURY: What per cent is this?

SHRI V. NARAYANASAMY: It is poverty ratio. ...*(Interruptions)*... I am referring to the poverty ratio.

SHRIMATI BRINDA KARAT: That is because of...

SHRI V. NARAYANASAMY: That is because of the development taking place in the rural areas on the basis of the schemes implemented by the State Governments with the help of the Central Government. That is the point I am trying to drive home. ...*(Interruptions)*... Kindly have patience. I understand your anguish. But, it is not only the Central Government's responsibility but the States also have a major role to play in developing the States. Therefore, Sir, it is cumulatively, both for developing the backward region and the development of the State. Sir, there are other programmes like the Hill Area Development Scheme and Border Area Development Scheme. So, through all these schemes, funds are being provided to the backward regions.

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में राज्यों के बीच आय-असमानता कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू करने के बारे में कहा है। इसके साथ-ही-साथ पिछड़े क्षेत्रों में अनुदान की बात भी कही गई है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि बिहार में, खास तौर पर जब वर्ष 2000 में बिहार का बँटवारा होने के बाद जो शेष बिहार बचा, वहाँ उद्योग के नाम पर, कल-कारखाने के नाम पर या infrastructure के नाम पर, कुछ भी नहीं रहा। वहाँ जो कुछ भी था, वह झारखंड में जा चुका है। जब बिहार का बँटवारा हुआ था, तब उसे विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी। उस समय केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार थी और आडवाणी जी गृह मंत्री थे।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री तारिक अनवर: उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, लेकिन वह विशेष पैकेज आज तक नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहूँगा कि यह जो असमानता है, इसको दूर करने के लिए, खासतौर पर बिहार को, जहाँ आज बाढ़, सूखा आदि हर तरह के जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, उन्हें बिहार झेल रहा है, वहाँ के लिए विशेष पैकेज देने की जो बात उस समय एन0डी0ए0 की सरकार ने किया था और 4 साल तक उनकी सरकार केन्द्र में रही, लेकिन उसने उसे कोई विशेष पैकेज नहीं दिया, तो क्या वर्तमान सरकार इस पर सोचेगी, विचार करेगी और उसे एक विशेष पैकेज देगी, ताकि यह असमानता दूर हो सके?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Member has mentioned about the Special Package for Bihar. Sir, I would like to inform the hon. Member that the hon. Chief Minister also wrote a letter to the hon. Prime Minister about the disaster and the havoc that has been caused by the Kosi river and the Government also sanctioned money for that. Though they demanded about Rs. 14,000 crores, the Government of India has given the money for the purpose of immediately ameliorating the problems faced by the region. Sir, as far as Bihar is concerned, no other State, when compared with other northern States, is getting a special plan. The Bihar

Special Plan was given by the Government of India, especially for rural electrification and also for irrigation facilities, which I have already mentioned, Rs. 1,000 crores every year.

SHRI TARIQ ANWAR: But it is not sufficient. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is a different matter.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Member is making a claim. Sir, as far as the Government of India is concerned, within the available resources, looking at the backward regions of various States, funds are being allocated. There are certain formulas given by the Planning Commission which have been accepted by the National Development Council. On that basis, the funds are being provided.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: श्रीमान्, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की जो घोषणा की है, माननीय मंत्री जी ने अभी उसका जिक्र किया था। इस बात के लिए मैं सबसे पहले सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को और राहुल गांधी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के सबसे पिछड़े और गरीब इलाके की तरफ, देर से ही सही, सरकार की नजर गयी। श्रीमान्, बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे पिछड़ा इसलिए है कि दुर्भाग्य से यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों में बंट गया और दोनों राज्यों की सरकारों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब दिया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: यह बिल्कुल गलत बात है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: यह बिल्कुल गलत बात है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रु द्रनारायण पाणि: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पाणि जी, प्लीज़ आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: पिछली सरकार की नीतियों के चलते ही यह पिछड़ापन है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल कर लीजिए, बस।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैंने तो सवाल करने के लिए ही यह बात उठाई थी और सच यही है। यह मैं नहीं कह रहा, आपके योजना आयोग के पिछले अनेक वर्षों के आंकड़े इस बात को कहते हैं कि बुंदेलखंड इस देश में सबसे गरीब और सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। अगर आज तक यह पिछड़ा है तो निश्चित रूप से यह उपेक्षा के कारण ही हुआ होगा और क्या हो सकता है? ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: किसकी उपेक्षा से...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: आप यहाँ से पैसा नहीं देते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: यह दिल्ली की सरकार ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: आप 50 सालों से पावर में हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिये। ...(**व्यवधान**)... You have to ask supplementary questions; please ask them. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, अब आप सवाल पूछ लीजिए, बस। ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अरे, तुम लोगों ने बुंदेलखंड का * किया है। ...(**व्यवधान**)... तुम लोगों ने बुंदेलखंड का * किया है। ...(**व्यवधान**)...

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

श्री शिवानन्द तिवारी: यह दिल्ली की सरकार जिसकी हुकूमत रही है ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: तुम लोगों ने क्या किया है? ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं?...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप लोग बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप लोग वेल में मत आइये। ...(**व्यवधान**)...

The House is adjourned till 12 o' clock.

The House then adjourned at forty-eight minutes past eleven of the clock till twelve noon.

————————

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Millennium Development Goals

†*102. MISS ANUSUIYA UIKEY: Will the Minister of HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the country has set a target to eradicate starvation by the year 2015 under Millennium Development Goals (MDG);

(b) if so, whether according to the experts of the United Nations Development Programme, it is not possible to achieve this target in the scheduled time-frame in the wake of global economic crisis; and

(c) if so, the details of the steps being taken to achieve this target in the scheduled time-frame?

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (KUMARI SELJA): (a) The Millennium Declaration signed in 2000 at United Nations, of which Government of India is also a signatory, lists 8 Millennium Development Goals (MDG). The first MDG is "Eradicate extreme poverty and hunger" by 2015. Specific targets for poverty and hunger are: (a) to halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than $1 a day and (b) to halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger.

(b) In a Report of United Nations Development Programme (UNDP), India, published in April, 2009, titled "Global Financial Crisis: Impact on India's Poor Some Initial Perspectives", Chapter 5 deals with the 'Impact of Financial Crisis on India's March Towards MDGs'. It mentions India's human development and achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), and says that if the national poverty line is used as the definition, the country is generally considered to be well on track to reduce the headcount ratio of poverty. However, due to global economic crisis, there

†Original notice of the question was received in Hindi.